



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, 16 जनवरी, 2008/26 पौष, 1929

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171001

**संख्या: 11-1/86(Lab)ID/07-Nahan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Bhagat Ram s/o Shri Bhadur Singh, Village Chamla, P.O. Baneti, Tehsil Nahan, District Sirmour, H.P. V/S The Divisional Forest Officer, Nahan Division, District Sirmour, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को

उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the demand notice dated 21-08-05 (Copy enclosed) raised by the President & General Secretary of Himachal Van Mazdoor Union (AITUC), Circle, Nahan before the Divisional Forest Officer, Nahan Division Nahan regarding regularisation of Shri Bhagat Ram s/o Shri Bhadur Singh, daily wage beldar is legal and justified? If yes, to what benefit of regularisation and relief the concerned workman is entitled to as per said demand notice. If not, its legal effect?”

-----  
शिमला-171001

**संख्या: 11-1/86(Lab)ID/07-Nahan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ramesh Kumar s/o Shri Albel Singh, Village Kotla Barog, P.O. Dedodevria, Tehsil Pachhad, District Sirmour, H.P. V/S M/S Shri Parwati Steel & Alloys & High Tech. Steel, Kala-Amb, District Sirmour, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the M/s Shri Parwati Steel & Alloys & High Tech. Steel, Kala-Amb, District Sirmour, H.P. to terminate the services of Shri Ramesh Kumar s/o Shri Albel Singh workman *w.e.f.* 30-05-2006 and not to pay him salary for the month of April & May, 2006 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

-----  
शिमला-171001

**संख्या: 11-1/86(Lab)ID/ 07-Nahan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kishan Singh s/o Shri Devi Ram, Village Talon, P.O. & Tehsil Nahan, District Sirmour, H.P. (2) Shri Sohan Lal s/o Shri Taru Ram, r/o Moh. Amarpur, Nahan, District Sirmour, H.P. (3) Shri Naranjan Singh s/o Shri Bishna Ram, r/o Moh. Amarpur, Nahan, District Sirmour, H.P. V/S The Executive Engineer (Mech.) HPPWD & IPH State Workshop, (Nahan Foundry), Nahan, District Sirmour, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त

अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the demand raised vide demand notices dated 15-06-2005 (copies enclosed) by S/Shri Kishan Singh, Sohan Lal and Naranjan Singh workmen before the Executive Engineer (Mech.) HPPWD & IPH State Workshop, (Nahan Foundry), Nahan, District Sirmour, H.P. is legal and justified? If yes, to what service benefits and relief the above aggrieved workmen are entitled from the above employer? If not, what its legal effects ?”

शिमला-171001

**संख्या: 11-23/84(Lab)ID/07-Una.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Vipin Kumar s/o Shri Harbans Lal, Village & P.O. Kuneran, Tehsil Amb, District Una, H.P. V/S Executive Engineer, H.P.S.E.B., Sub Division, Gagret, Tehsil Amb, District Una, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Vipin Kumar s/o Shri Harbans Lal workman by the Executive Engineer, H.P.S.E.B., Sub Division, Gagret, Tehsil Amb, District Una, H.P. w.e.f. 10-06-06 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या: 11-23/84(Lab)ID/07-Una.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Narinder Singh s/o Shri Laxman Dass, Village Kharoh, P.O. Gindpur Malan, Tehsil Amb, District Una, H.P. V/S Executive Engineer, H.P.S.E.B., Division, Amb, District Una, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Narinder Singh s/o Shri Laxman Dass, workman by the Executive Engineer, H.P.S.E.B., Division Amb, District Una, H.P. w.e.f. 25-08-96 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

-----  
शिमला-171001

**संख्या: 11-1/13(Lab)ID/07-Una.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Surinder Kumar s/o Shri Balbir Chand, Village & P.O. Dhamandri, Tehsil & District Una, H.P. V/s The assistant Engineer, IPH Sub Division, Amb, District Una, H.P.के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Surinder Kumar s/o Shri Balbir Chand, workman by the Assistant Engineer, IPH sub Division, Amb, District Una, H.P. w.e.f. 26-06-2004 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

-----  
शिमला-171001

**संख्या: 11-1/13(Lab)ID/07-Una.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Mandir Singh, Village & P.O. Saloh, Tehsil & District Una, H.P. V/s The assistant

Engineer, IPH Sub Division, Amb, District Una, H.P.के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Mandir Singh workman by the Assistant Engineer, IPH sub Division, Amb, District Una, H.P. w.e.f. 26-06-2004 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

-----  
शिमला-171001

**संख्या: 11-1/13(Lab)ID/ 07-Una.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Waryam Chand s/o Late Shri Ram Lal, Village Jhalera, P.O. Rainsary, Tehsil & District Una, H.P. V/s The Assistant Engineer, IPH Sub Division, Amb, District Una, H.P.के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Waryam Chand s/o Late Shri Ram Lal workman by the Assistant Engineer, IPH Sub Division, Amb, District Una, H.P. w.e.f. 26-06-2004 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

**संख्या: 11-1/13(Lab)ID/07-Una.**—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Jagdish Ram s/o Shri Suchha Ram, Village & P.O. Nangran, Tehsil & District Una, H.P. V/s The Assistant Engineer, IPH Sub Division, Amb, District Una, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Jagdish Ram s/o Shri Suchha Ram workman by the Assistant Engineer, IPH Sub Division, Amb, District Una, H.P. w.e.f. 26-06-2004 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या: 11-23/84(Lab)ID/07-Una.**—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sadik Mohammad s/o Mohammad Baksh, Village Baduhi, P.O. Chowki-minar, Tehsil Bangana, District Una, H.P. V/S Divisional Forest Officer, Forest Division, Una, District Una, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Sadik Mohammad s/o Mohammad Baksh workman by the Divisional Forest Officer, Forest Division, Una, District Una, H.P. w.e.f. Year, 2001 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

**संख्या: 11-1/13(Lab)ID/ 07-Una.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Hem Raj s/o Shri Kashmir Singh, Village Rampur, Tehsil & District Una, H.P. V/S Executive Engineer, Transmission Division, H.P.S.E.B. Rakker, Una, District Una, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Hem Raj s/o Shri Kashmir Singh workman by the Executive Engineer, Transmission Division, H.P.S.E.B. Rakker, Una, District Una, H.P. *w.e.f.* 26-02-97 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Parwanoo.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Krishan Lal s/o Shri Bhalkhu Ram, Village Kared Dadhayan, P.O. Dhalwan, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S Managing Director, M/S Modesto Polymers Private Limited, Plot No.13, Sector-5, Parwanoo, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Krishan Lal s/o Shri Bhalkhu Ram workman by the Managing Director, M/S Modesto Polymers Private Limited, Plot No.13, Sector-5, Parwanoo, District Solan, H.P *w.e.f.* 17-02-06 without holding any domestic enquiry and without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Parwanoo.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Vrinder Kumar s/o Shri Padam Singh, C/O Shri Narinder Kumar, R/O House No.26/12, Tivvi Mohalla, Kalka, Octroi Post No.4, Haryana. V/S Genaral Manager, M/S Pronto Steering Limited, Plot No.3-4&5, Industrial Area, Sector-V, Parwanoo, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Vrinder Kumar S/O Shri Padam Singh workman by the Genaral Manager, M/S Pronto Steering Limited, Plot No.3-4&5, Industrial Area, Sector-V, Parwanoo, District Solan, H.P w.e.f. 07-01-06 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Om Parkash S/O Shri Jia Lal Verma, Village Budman, P.O. Bhumati, Tehsil Arki, District Solan, H.P. V/S Executive Engineer, HPSEB, Electrical Division, Parwanoo, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Om Parkash S/O Shri Jia Lal Verma workman by the Executive Engineer, HPSEB, Electrical Division, Parwanoo, District Solan, H.P. w.e.f. 26 08-97 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”



**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि S/Shri Sarvjeet Singh S/O Shri Jasmer Singh, Devinder Chand S/O Shri Gopal Chand, Ramesh Kumar S/O Shri Mohan Lal, Devki Nandan S/O Shri Narain Dass V/S Pardhan/Secretary, Gram Panchyat Dharampur, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of S/Shri Sarvjeet Singh S/O Shri Jasmer Singh, Devinder Chand S/O Shri Gopal Chand, Ramesh Kumar S/O Shri Mohan Lal, Devki Nandan S/O Shri Narain Dass workman by the Pardhan/Secretary, Gram Panchyat Dharampur, District Solan, H.P w.e.f. 31-05-05 without serving them charge sheet and without holding any domestic enquiry and without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workmen are entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Suresh Kumar S/O Shri Nanak Chand, Village Sher Chirag, P.O. Jonaj, Tehsil & District Solan, H.P. V/S Executive Engineer, Electrical Division, HPSEB, Saproon, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Suresh Kumar S/O Shri Nanak Chand workman by the Executive Engineer, Electrical Division, HPSEB, Saproon, District Solan, H.P. w.e.f. 05-09-99 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Dhanbir Singh S/O Shri Nain Singh, Village Kuthah, P.O. Bhwai, Tehsil Sangrah, District Sirmour, H.P. V/S Executive Engineer, I.& P.H. Division, Nahan, District Sirmour, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Dhanbir Singh S/O Shri Nain Singh workman by the Executive Engineer, I.& P.H. Division, Nahan, District Sirmour, H.P w.e.f. 01-09-98 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि (1) Shri Geeta Ram S/O Shri Ram Lal (2) Shri Harish Kumar S/O Shri Surjit Singh (3) Shri Suresh Kumar S/O Shri Ratti Ram V/S (1) Chairman, Market Committee, Solan, H.P. (2) Secretary, Market Committee Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of (1) Shri Geeta Ram S/O Shri Ram Lal (2) Shri Harish Kumar S/O Shri Surjit Singh (3) Shri Suresh Kumar S/O Shri Ratti Ram workman by the (1) Chairman, Market Committee, Solan, H.P. (2) Secretary, Market Committee Solan, H.P w.e.f. 01-12-03, 21-10-03 and 01-12-03 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the aggrieved workmen are entitled to?”

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rakesh Kumar Sharma S/O Shri Ishwara Nand, Village Baryari, P.O. Delagi, Tehsil & District Solan, H.P. V/S (1) Director, Technical Education, Directorate of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. (2) Principal Industrial Training Institute, Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Rakesh Kumar Sharma S/O Shri Ishwara Nand, Instructor by the (1) Director, Technical Education, Directorate of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. (2) Principal Industrial Training Institute, Solan, H.P w.e.f. 22-09-97 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation Shri Rakesh Kumar Sharma S/O Shri Ishwara Nand, Instructor is entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kuldeep Singh S/O Shri Mohinder Singh, Village & P.O. Trilokpur, Tehsil Nahan, District Sirmour, H.P. V/S Executive Engineer, HPSEB (T&C), Shakti Nagar, Tehsil Nahan, District Sirmour, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Kuldeep Singh S/O Shri Mohinder Singh workman by the Executive Engineer, HPSEB (T&C), Shakti Nagar, Tehsil Nahan, District Sirmour, H.P w.e.f. 11-11-2001 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sandeep Kumar S/O Shri Jagdish Ram, Village Badho, Tehsil Amb, District Una, H.P. V/S Executive Engineer, Flood protection, I.& P.H. Division, Gagret, Tehsil Amb, District Una, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Sandeep Kumar S/O Shri Jagdish Ram workman by the Executive Engineer, Flood Protection, I.& P.H. Division, Gagret, Tehsil Amb, District Una, H.P w.e.f. June, 1995 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sunil Dutt S/O Shri Yashpaul Sharma, Village Babhar, Tehsil & District Una, H.P. V/S Executive Engineer, Tubewell Division, I.&P.H. Department, Gagret, District Una, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination of services of Shri Sunil Dutt S/O Shri Yashpaul Sharma workman by the Executive Engineer, Tubewell Division, I.& P.H. Department, Gagret, District Una, H.P. w.e.f. 01-05-98 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि General Secretary, Nahan Foundary Mazdoor Panhyat Nahan, District Sirmour, H.P V/S (1) Superintending Engineer, H.P.P.W.D. & I.P.H. State workshop, Nahan Foundary Nahan, District Sirmour, H.P. (2) Executive Engineer (Mech.), H.P.P.W.D. & I.P.H., State workshop Nahan Foundary Nahan, District Sirmour, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the demand raised by the General Secretary, Nahan Foundary Mazdoor Panhyat Nahan, District Sirmour, H.P on behalf of S/Shri Rattan Lal & 22 others workmen whose names are given therein the demand notice dated 04-04-2005 (Copy enclosed) from the (1) Superintending Engineer, H.P.P.W.D. & I.P.H. State Workshop, Nahan Foundary Nahan, District Sirmour, H.P. (2) Executive Engineer (Mech.), H.P.P.W.D. & I.P.H., State workshop Nahan Foundary Nahan, District Sirmour, H.P as per demand notice is legal and justified? If yes, from which date the aggrieved workmen are entitled for granting pay scale and other service benefits from the above employer?”

शिमला-171001

**No. 11-2/93(Lab) I.D./07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Bikram Singh S/O Shri Nathu Singh, R/O House No.26/1, Ward No.I, Tibbi Mohalla, Kalka, District Panchkulla, Haryana. V/S M/S Purolator India Limited, Sector-I, Parwanoo, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the retirement w.e.f. 30-06-2003 of Shri Bikram Singh S/O Shri Nathu Singh workman after attaining the age of 55 years instead of attaining the age of 60 years as per Certified Standing Orders of the management of M/S Purolator India Limited, Parwanoo, District Solan, H.P. is legally maintainable and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या:11-2/93(Lab) ID/07- Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि-S Shri Kewal Kishor Thakur S/O Shri Amin Chand Village and P.O. Meda Majra, House No. 4-A, Ajoli, Tehsil Anandpur sahib, District Ropar (Punjab). V/S – M/S. Punjab Laminates Pvt. Ltd. Mehatpur District Una H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the dismissal from service of Shri Kewal Kishor S/O Shri Amin Chand w.e.f. 01.12.2004 vide letter dated 01.12.2004 by the Management of M/Spunjab Laminates Pvt. Ltd., Mehatpur, District Una (H.P.)) is legal and justified ? If not, to what seniority, back wages, service benefit and relief the concerned workman is entitled to ?”

शिमला-171001

**संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ravi Dutt S/O Late Shri Garibu Ram ,VPO. Nagali, Tehsil Kandaghat District Solan H.P. V/S (1) Executive Engineer, HPSEB Division, Solan District Solan H.P. (2) Assistant Engineer, Electrical Sub Division, HPSEB, Kandaghat District Solan, H.P के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का

14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the termination w.e.f. 25.07.98 and again w.e.f. 26.03.2000 vide notice dated 13.07.98 and 03.03.2000 respectively of Shri Ravi Dutt S/O Late Shri Garibu Ram daily wage workman by the (1) Executive Engineer, HPSEB Division, Solan District Solan H.P. (2) Assistant Engineer, Electrical Sub Division, HPSEB, Kandaghat District Solan, H.P is legal & justified? If not, to what seniority, back wages, service benefits the concerned workman is entitled to?”

शिमला-171001

**संख्या :11-2/93( Lab)ID/ 07-Solan.**— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Jitender Singh S/O Shri Mahinder Singh R/O Village Boriwala P.O. Kaulanwala Bhood Tehsil Nahan District Sirmour (H.P) V/S The Executive Engineer, HPSEB Division Nahan District Sirmour (H.P.) नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the plea of the Executive Engineer, HPSEB, Division Nahan District Sirmour H.P that Shri Jitender Singh S/O Shri Mahinder Singh daily wage workman had left the job of his own accord after 31.03.95 due to absenteeism is legal & justified?, if not, to what back wages, seniority, service benefits and relief the concerned workman is entitled to?”

Sd/-  
Labour Commissioner.

वहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

9 जनवरी, 2008

**संख्या: विद्युत.-छ-(5)-19/2007.**— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की

धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पशगांव, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0 में गानवी जल विद्युत परियोजना स्टेज-11 की सड़क एवं इन्टेक एरिया के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव: एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्ध के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला, हिमाचल प्रदेश को एतद्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

3 इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, थिसिल बैंक भवन, शिमला, हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4 भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला-3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
शिमला	रामपुर	पशगांव	503	0—03—61
			602	0—14—55
			601	0—08—61
			598	0—20—93
			591	0—38—72
			737 / 2 / 2 / 1	0—00—52
			कुल कित्ता—6 कुल रकबा—	

आदेशद्वारा,  
हस्ता / -  
प्रधान सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 14 जनवरी, 2008

संख्या:सिंचाई11-82/2007-हमीरपुर.- यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बहल रतनू, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना बहल रतनू पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी



अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

### विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र हैक्टेयर में
हमीरपुर	बड़सर	बहल रतनू	22	0-02-64 है०

शिमला-171002, 14 जनवरी, 2008

**संख्या:सिंचाई11-85/2007-हमीरपुर.-** यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टिक्कर व मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में दो जल भण्डारण टैंक पेयजल योजना बल्ला राठियां के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

### विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	मौजा	खसरा न०	क्षेत्र कनाल मरला में
हमीरपुर	सुजानपुर	टिक्कर	भलेठ	571	15-6 क० म०

**संख्या:सिंचाई-11-84/2007-बिलासपुर-** यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव डढोग, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना खुर्द मैथी के जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

### विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र बिघा-बिस्वा में
बिलासपुर	सदर	डढोग	2/1	0-5

शिमला-171002 14 जनवरी, 2008

**संख्या:सिंचाई: 11-168/2007-सुन्दरनगर-** यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल रौहण, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल पम्प हाउस के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

### विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टेयर में
मण्डी	सरकाघाट	रौहण/358	791/1	0-00-72

आदेश द्वारा,  
हस्ता/-  
प्रधान सचिव।

**DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE & FORESTRY,  
SOLAN –173230**

**“GENERAL ADMINISTRATION BRANCH”**

**NOTIFICATION**

*9 January, 2008*

**No.UHF.Regr.GA/5-28/07/-25099-25153.**— In exercise of the powers vested under Section 54 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987) and with the approval and assent of the Chancellor, the Board of Management of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry is pleased to make the following amendment in Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987.

**FORTIETH AMENDMENT IN THE STATUTES OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR  
UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987**

(As assented to by the Chancellor (Governor, Himachal Pradesh) vide letter No. 45-3/75 GS-III dated 13th November, 2007.

**AN AMENDMENT**

To amend the First Statutes of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987.

- (1) This amendment may be called the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, Statutes, 1987 (Fortieth amendment, 2008)
- (2) It shall come into force with immediate effect.
- (3) The following addition shall be made in Statute 3.11, 4.6, 5.8, 5.9 & 5.10.

**Addition to Statutes 3.11, 4.6, 5.8 and 5.9:** The following Note shall be inserted at the end of Statutes 3.11, 4.6, 5.8 and 5.9, respectively:

*Note:* The Vice-Chancellor, in addition to the existing composition of Selection Committees, may endeavour as far as possible, to nominate one Officer of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Category on Selection Committees where the candidate(s) belonging to these categories is/are appearing for interview.

**Addition to Statute 5.10:** The following proviso shall be inserted at the end of Statute 5.10:

“Provided that the Vice Chancellor may endeavour as far as possible, to nominate one Officer of Scheduled Caste /Scheduled Tribe category in respective Promotion Committees, in addition to the existing composition, where the candidate(s) belonging to these categories is/are in the zone of consideration”.

By order,  
Sd/-  
REGISTRAR.

## शहरी विकास विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 11 जून, 200

**संख्या:एल.एस.जी.-ए(1)-3/2007.-** हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची-1 को संशोधित करने तथा नगर पंचायत मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को नगर परिषद् घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त प्रस्तावित घोषणा के बारे में आक्षेप करने की इच्छा रखता हो, तो वह अपने आक्षेप, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को, उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्रस्तुत करे।

आदेश द्वारा,  
हस्ता/-  
प्रधान सचिव।

-----  
[Authoritative English text of the Government notification No.UD-A(1)-3/2007, dated 11.06.2007, as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India]

## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, 11 June, 2007

**No. UD-A(1)-3/2007.—** In exercise of the powers conferred by second proviso to sub section(2)of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994(Act No.13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh Proposes to amend Schedule-I and to declare Nagar Panchayat, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh as Municipal Council;

Any person who desires to object to the proposed declaration, should submit his objections in writing to the Principal Secretary(Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Kullu within thirty days from the date of the publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh(extra-ordinary) .

By order,  
Sd/-  
Principal Secretary.